

पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत का प्रतिनिधिमंडल



भारत सरकार पहलगाम की घटना पर दुनिया को जानकारी देने के लिए सांसदों के आठ समूह भेज रही है। हर समूह में अलग-अलग पार्टियों के कम से कम पाँच सांसद होंगे। उनके साथ एक सीनियर राजनयिक भी होगा। ये समूह अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ (EU), रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका और खाड़ी देशों जैसे अहम शहरों में जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये प्रतिनिधिमंडल 21-22 मई को खाना होगा। ये सांसद पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताएंगे। कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सांसद नहीं हैं। इसी तरह राजनयिक दल सांसदों की मदद करेंगे। इन लिस्ट में पूर्व विदेश सचिव एच.वी. श्रृंगला, फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत जावेद अशराफ और मोहन कुमार, और जापान में पूर्व राजदूत सुजान चिलनॉय जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

सलमान खुर्शीद दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया जाएंगे

कांग्रेस के सांसद सलमान खुर्शीद दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया जाएंगे। वे दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में बात करेंगे। जेडीयू के सांसद संजय झा और श्रृंगला भी एक

समूह का नेतृत्व करेंगे। सुप्रिया सुले (एनसीएसपी), और श्रीकांत शिंदे (शिवसेना) भी एक-एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। सुले के समूह में राजीव प्रताप रूडी (बीजेपी) अनुराग ठाकुर (बीजेपी), मनीष तिवारा (कांग्रेस), बृज लाल (बीजेपी) और तेजस्वी सूर्या (बीजेपी) शामिल हैं। असदुद्दीन औवैसी (आईएमआईएम) भी एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। डीएमके नेता कनिमोड़ी रूस जाने वाले समूह का नेतृत्व करेंगे। आरजेडी सांसद प्रेम चंद गुप्ता उनकी टीम में हैं। शशि थरूर अमेरिका में सांसदों की संघालेंगे कमान कांग्रेस सांसद शशि थरूर अमेरिका जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रुसेल्स में EU के मुख्यालय का दौरा करने वाले समूह का नेतृत्व कर सकते हैं। बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा, टीडीपी के लोकसभा सांसद लावु श्री कृष्णदेवरायण और बीजेपी सांसद जय पांडा भी इन समूहों में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के आर.एस. प्रसाद के पश्चिम एशिया जाने की संभावना है, जिसमें

सऊदी अरब भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय भी एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय भी बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि वे इतनी लंबी यात्रा करने के लिए ठीक नहीं हैं। इन समूहों को भेजने का मकसद है कि भारत सरकार दुनिया को पहलगाम की घटना और रूपांतरण सिद्धूर के बारे में सही जानकारी दे सके। सरकार चाहती है कि दुनिया को पता चले कि असल में क्या हुआ था और भारत इस मामले में क्या कर रहा है। अलग-अलग पार्टियों के सांसदों को भेजने से यह भी पता चलता है कि इस मुद्दे पर पूरा देश एक साथ है। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि दुनिया के बड़े देशों को इस बारे में सही जानकारी मिले, ताकि कोई गलतफहमी न हो।

सरकार ने विपक्षी दलों के सांसदों को विदेश भेजने की योजना बनाई है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है। यह योजना, पहलगाम में हुए अलंकृत हमले के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए है। सरकार अलग-अलग देशों में सर्वदलीय संसदीय

सांसदों का 8 ग्रुप दुनिया को बताएगा सच

प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। बताया जा रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया। उन्होंने खड़गे से इस योजना में उनकी पार्टी की भागीदारी का अनुरोध किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'रकूल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की और पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के लिए 4 संसदों के नाम प्रस्तुत करने की कहां। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोरोई, डॉ. सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार का नाम आगे बढ़ाया है। सरकार ने अपने सांसदों, कुछ पूर्व मंत्रियों और राजनयिकों से भी बात की है। सरकार चाहती है कि वे भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनें। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने विपक्ष के कई सांसदों और पूर्व मंत्रियों से संपर्क किया है। इनमें शशि थरूर, मनोप तिवारी, अमर सिंह, सत्यना खुराशी (कांग्रेस) शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद (डीपीएम), जॉन ब्रिटायस (CPI-M), असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM) और प्रियंका चतुर्वेदी (UBT) को भी संपर्क किया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, अब अचानक, पीएम ने पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत का रुख समझाने के लिए बहु-दलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने का फैसला किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में खड़ी रहती है और बीजेपी की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करती है। इसलिए, आइएनसी निश्चित रूप से इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होगा।



मोदी सरकार की नरसिम्हा राव वाली कूटनीति

सरकार फलगाम में आंतकवादी हमले के जवाब में चलाए गए 'आपरेशन सिंदूर' के बाद आक्रामक राजनीतिक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत वैश्विक मंच पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रभावित आतंकवाद को बेनकाब किया जाएगा। खास बात है कि इस काम के लिए मोदी सरकार ने नरसिम्हा राव की कूटनीति के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। अगले साप्ताह से निम्न देशों में कई बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। यह ठीक उसी तर्ज पर जब नरसिम्हा राव ने यूनान में कश्मीर मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा था।

1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने जिनैवा में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार से जुड़े सत्र में एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया था। इसका उद्देश्य कश्मीर समस्या पर भारत का पक्ष रखना और पाकिस्तान द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को विफल करना था, जिसमें नई दिल्ली की निंदा की जाती। उस समय यह प्रयास बहुत

पीवी नरसिम्हा राव ने विदेश नीति के धुरंधर माने जाने वाले विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रतिनिधि मंडल का प्रमुख नियुक्त किया था। उनके साथ कश्मीर के फारुक अब्दुल्ला और राव सरकार के विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद भी थे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में गहन जानकारी के साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत के तत्कालीन राजदूत हामिद अंसारी को भी शामिल किया गया था।

राव के कदम से परेशान थे खुर्शीद ?

अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने छह दशक से अधिक के राजनीतिक करियर में हमेशा व्यक्तिगत समीकरणों पर भरोसा किया। उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ उनकी नजदीकी हमेशा उनके संबंधित राजनीतिक दलों में उत्तुक्ता भरी चर्चा का विषय रही। राव की तरफ से वाजपेयी को नियुक्त होने के कदम को उनकी पार्टी के भीतर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद जिनैवा में वाजपेयी के अधीन काम करने से विशेष रूप से परेशान थे।

गहमर गांव से आर्मी में 15000 लोग

मां खाती हैं बच्चों को फौजी बनाने की कसम

8 मई, रात के 10 बज रहे होंगे। कश्मीर से मेरे बेटे नीरज का फोन आया। वो उरी सेक्टर में बॉर्डर पर तैनात है। उसने बताया- पापा यहां फायरिंग तेज हो गई है। ड्यूटी बढाई जा रही है। कुछ दिनों तक फोन नहीं कर पाऊंगा। आप सब पंशान मत होना। 3 दिन तक कोई फोन नहीं आया। 11 मई को गोलीबारी थमी। तब बेटे का दोबारा फोन आया। जब पता चला कि सब ठीक है। तब थोड़ा सुकून मिला।' फौजी बेटे की बात करते हुए 56 साल के दिनेश सिंह का दिल गर्व से भर जाता है। वो कहते हैं- खुशी होती है जब किसी को बताता हूं कि मेरा बेटा सेना में है। वो देश की रक्षा के लिए सरहद पर ड्यूटी कर रहा है। नीरज, यूपी के गाजीपुर में गहमर गांव के रहने वाले हैं। उनकी ही तरह गांव के 90 घरों के 200 से ज्यादा बच्चे इस वक्त जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात हैं।

ये सभी परिवार गांव की 100 साल पुरानी उस परंपरा को निभा रहे हैं, जिसमें मां बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें 'फौजी' बनाने की कसम खाती हैं। गांववालों के मुताबिक, ब्रिगेडियर से लेकर सिपाही तक गांव में 5 हजार से ज्यादा डायरेक्ट फौजी और करीब 10 हजार लोग सेना में ड्यूटी कर रहे हैं।

15 हजार से ज्यादा सैनिक देने वाले गांव की कहानी...

यूपी में गाजीपुर से 40 किमी दूर पड़ता है गहमर गांव। आबादी के लिहाज से ये एशिया का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन ये इसकी पहचान नहीं है। इसकी पहचान है देशभक्ति का जूनून। यहाँ हर घर में कोई न कोई व्यक्ति सेना में है या रह चुका है। इस गांव ने भारतीय सेना को अब तक 15 हजार से ज्यादा सैनिक दिए हैं। इसी वजह से लोग गहमर को 'फौजियों वाला गांव' भी कहते हैं।

गहमर में सेना में जाने की तैयारी में जुटे युवाओं से भारत-पाकिस्तान के बीच बने हालात पर बात की। 90 साल के बंशीधर सिंह 1971 की जंग लड़ चुके हैं। ये कहते हैं कि सरकार अगर इजाजत दे तो ये आज भी बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान से युद्ध लड़ सकते हैं। गांव में घुसते ही हर गेट पर सैनिकों के नाम लिखे मिले। हर घर में फौजियों की तस्वीरें, वॉलियाँ और सेना के मेडल अलमारियों में सजे हैं। यहां के 50 से ज्यादा लोग पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की जंग से लेकर कारगिल तक की लड़ाई लड़ चुके हैं।

72 साल के पूर्व सूबेदार मेजर वीरबहादुर सिंह 1977 से लेकर 2008 तक इंडियन आर्मी में रह चुके हैं। भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात को लेकर ये कहते हैं, 'भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। 4 से 5 दिन में ही दुश्मन देश के होश फांखता

ही गए। उसके पास अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना का कोई मुकाबला ही नहीं है। बीते 10 साल में आर्याम में जो नए हथियार और तकनीकें शामिल हुई हैं, उसका फायदा ये हुआ कि हमने भर में ही पाकिस्तान ने हमारे आगे धुने टेक दिए और संघर्ष विराम जैसी स्थिति बन गई। हमारी सेना ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया।’

हालांकि, वीर बहादुर को एक बात का मलाल भी है। ये कहते हैं, ‘ये वक्त था कि इस बार हम पीओके को भारत में मिला सकते थे। अगर ऐसा हो गया होता, तो सीमापार से होने वाली आतंकी घटनाएं हमेशा के लिए खत्म हो सकती थीं।’

चलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ है। मैं भारतीय जवानों से यही कहूंगा कि आप लोग इसी तरह डटे रहो और दुश्मन को जवाब देते रहो। जय हिंद की सेना।’

गहमर गांव से भारतीय सेना में 42 लेफ्टिनेंट से लेकर 23 ब्रिगेडियर तक के अधिकारी रहे हैं। मौजूदा समय में भी 45 कर्नल रैंक के अधिकारी सेना में एक्टिव हैं। गांव 22 छोटे टोलों में बंटा हुआ है। हर टोले का नाम किसी न किसी सैनिक के नाम पर रखा गया है, जो गांव के सैन्य इतिहास को दिखाता है।

गांव के चंदन सिंह 2006 से लेकर 2015 तक लेह और जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में पोस्टेड थे। ये सीजफायर पर असहमति जताते हुए कहते हैं, ‘आज पाकिस्तान जितना बोल पा रहा है, कहीं न कहीं उसकी वजह चीन का उसके साथ खड़े होना है। आज हमने अमेरिका के दबाव में आकर युद्ध विराम कर लिया।

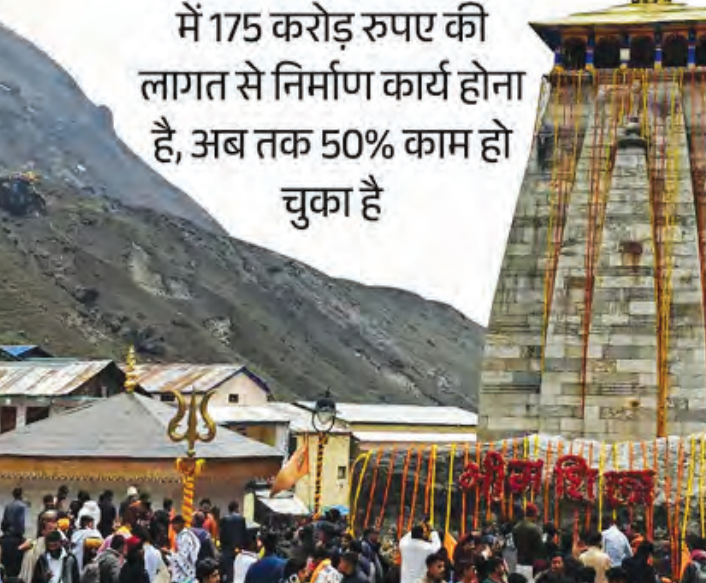
ये बहुत दुखद है। एक भूपूर्व सैनिक होने के नाते उस रात मुझे नींद नहीं आई।’

16 मार्च 2021 को लोकसभा में बताया गया कि देश में कुल 11 लाख 51 हजार 726 जवान सीमा पर तैनात थे। इसमें से 14.5%, यानी 1 लाख 67 हजार 557 सैनिक अकेले यूपी के हैं। दूसरे नंबर पर 7.7%, यानी 89 हजार 88 जवानों के साथ पंजाब है। तीसरे नंबर पर 87 हजार 835 जवानों के साथ महाराष्ट्र है। यूपी के गाजीपुर जिले से मौजूदा समय में 10,350 सैनिक सेना के अलग-अलग हिस्सों में तैनात हैं। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी गहमर गांव से है।

गांव में किसी भी परिवार से मिलिए, एक बात कॉमन है। दादा रियाज होकर खेती बाड़ी कर रहे हैं और उनका बेटा या पोता बॉर्डर पर ड्यूटी में तैनात है। गहमर के लोग 1914 से लेकर 1919 में पहले विश्व युद्ध में भी शामिल हुए। उस वक़्त अंग्रेजों के खिलाफ गांव के 228 लोगों ने जंग लड़ी थी, जिसमें से 21 शहीद हो गए।

तबाही के बाद केदारनाथ अब कितना सेफ

मंदिर की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सेफ्टी वॉल और चौड़े रास्ते, किन्ता कुछ बदला '2013 में बाढ़ वाले दिन रामबाड़ी में था। हर तरफ सिर्फ पानी और मलबा दिख रहा था। मेरी आंखों के सामने ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ बहा ले गया। कुछ ही सेकेंड में होटल, दुकानें, लोग और जानवर सब बह गए। लगने लगा था कि अब कभी यहाँ लोग नहीं आएंगे, लेकिन 13 साल बाद देखो...सड़के चौड़ी हो गई, रास्ता चकाचक है। बुजुर्गों को पालकी में बैठाकर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा करवाने वाले राकेश थापा खुश हैं कि सरकार ने पूरा सिस्टम ठीक कर दिया है। इससे उन्हें भी सुकून हो गया है। 2 मई से केदारनाथ धाम के कापाट खुला दिए गए हैं। 17 मई तक लगभग चार लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। अनुमान है कि इस साल चारधाम यात्रा में 25 लाख लोग सिर्फ केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचेंगे। गढ़वाल कमिश्नर के मुताबिक, मंदिर तक पहुंचने का रास्ता चौड़ा किया जा रहा है। मंदिर के पीछे और मंदाकिनी-सरस्वती नदियों के किनारे 3 लेयर सेफ्टी वॉल बनाई गई है। इससे बाढ़ के हालात में मंदिर सेफ रहेगा। इतने श्रद्धालुओं को उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति कैसे संभाल रहे हैं? डेवलपमेंट के डिजिटल पर है? सुरक्षा इंतजाम कैसे है? 2013 में पूरी तरह तबाह हो चुकी केदार घाटी अ पहले की तुलना में यात्रियों के लिए किन्ती सेफ है? इसकी पडताल करती रिपोर्ट....। उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, 2 मई को कापाट खुलने के बाद पहला दिन करीब 31 हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। 15 मई तक करीब 3.34 लाख श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक, चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा फुटफॉल केदारनाथ में ही होता है। पिछले साल यात्रा में शामिल हुए 46 लाख लोगों में से 1 लाख यात्रियों ने अकेले केदारनाथ के दर्शन किए। ऐसे में जून से अगस्त के बीच अगर मौसम सही रहता है, तो इस बार 25 लाख ज्यादा लोगों के केदारनाथ धाम पहुंचने का अनुमान है। धाम में 7 हजार लोगों के ठहरा का इंतजाम है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का मानना है कि केदारनाथ आपदा के बाद धाम में हुई रिडेवलपमेंट ने तीर्थ यात्रियों का भरोसा पक्का से दोगुना कर दिया है। रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट व 80% काम पूरा हो चुका है। इसमें 21 करोड़ की लागत से 18 किमी का गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग, आपदा में तबाह हुए हिस्सों का मरम्मत और मंदाकिनी-सरस्वती नदियों के किनारे नए घाट बनाना शामिल है। तीर्थयात्रियों का लोड मैनेज करने के लिए रामबाड़ी से गरुडचट्टी तक 5.35 किमी लंबा और 1.8 मीटर



2022 से 2025 तक थर्ड फेज
में 175 करोड़ रुपए की
लागत से निर्माण कार्य होना
है, अब तक 50% काम हो
चुका है

योड़ा रास्त बनाया जा रहा है। विनय शंकर पांडे कहते हैं, '4,081 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रोपवे को पल्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यांनी पीपीपी मॉडल के जरिए डेवलप कर रहे हैं। अभी ये प्रोजेक्ट टेंडर स्टेज पर है। प्रक्रिया पूरी होते ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा।'

21 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ रोप-वे परियोजना का शिलान्यास किया था। सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने के लिए यात्रियों को 18 किमी पैदल चलना पड़ता है। इसमें करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं। रोप-वे बन जाने के बाद केदारनाथ यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ की दूरी सिर्फ 36 मिनट में पूरी हो सकेगी। करीब 1800 यात्रा 1 घंटे में केदारनाथ धाम पहुंच सकेंगे।

उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित, दूर दूरे ट्रैवल एजेंट, होटल बिजनेस, पिछु और छोटे दुकानदारों के मिलकर यात्रा 2 लाख परिवारों की रोजी-रोटी के केदारनाथ यात्रा पर निर्भर है। आपदा के बाद और कोरोना काल में केदारनाथ धाम के कपास बंद रहे। उस दौरान यहां के छोटे दुकानदारों के आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी। 2022 से लगातार केदारनाथ आने वाले यात्रियों का आंकड़ा 15 लाख से ऊपर पहुंच रहा है। इस बार ये आंकड़ा बढ़ सकता है। केदारनाथ मंदिर में बीते 40 साल से पूजा-पाक करा रहे राम प्रकाश पुरोहित का घर और दुकान 2013 में आई बाढ़ में बर्बाद गए थे। सरकार से मिली राहत राशि से उन्होंने दोबारा दुकान शुरू की है। राम प्रकाश कहते हैं, '2013 में आई बाढ़ में मेरे सामने ही 2-3 मिनट में सब कुछ बर्बाद हो गया। उस वक़्त न

लग रहा था कि शायद अब हम कभी य दोबारा नहीं बस पाएंगे। सरकार ने यहां तेजी रिडेवलपमेंट करवाया है। धाम तक जाने वाला आस्था पथ पूरा बन चुका है।' 'पहले गौरीकुंड से यात्रा छोटी थी, लेकिन यात्रियों को बहुत परेशानी होती थी। छोटे-छोटे रास्तों पर खच्चर और लोग साथ चलते थे इसमें जानवरों से टक्कर लाकर गिरने व खतरा रहता है। कई बार खच्चर खुद फिसल कर गिर जाते थे। अब मंदिर तक जाने के लिए नया रास्ता बन गया है। ये पहले से 4 किमी लंबा जरूर है, लेकिन काफी चौड़ा है। इस खच्चर और यात्री आसानी से साथ-साथ चला सकते हैं।' पिछले साल केदारनाथ यात्रा लोकल बिजनेस के लिहाज से भी काफी अच्छी रही। घोड़े खच्चरों, हेलिकॉप्टर से यात्रा और पैदल यात्रियों की बढ़ी संख्या से लगभग 190 करोड़ रुपए कारोबार हुआ। 2022 में केदारनाथ धाम अकेले खच्चर और पालकी-पिंडू व्यवसायियों करीब 109 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया था। इस साल इससे ज्यादा कमाई अनुमान है। चार धामों में सबसे मुश्किल पैदल यात्रा केदारनाथ की है। यहां हमेशा खतरा बना रहता है। 16-17 जून 2013 की त्रासदी के बाद यहां समय-समय पर रकावटें आती रही हैं। पिछले साल 31 जुलाई को केदारनाथ रूट पर भारी बारिश के कारण यात्रा रोक दी गई थी। इसके तुरंत बाद 4 अगस्त को यहां भयानक लैंडस्लाइड हुई, इसमें 15 हजार यात्री फंस गए और 5 यात्रियों को मौत हो गई थी। ऐसी स्थिति

से निपटने के लिए इस बार केदारनाथ में क्या अरेंजमेंट है? इस पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे कहते हैं, 'फ़िलहले साल केदारनाथ में भारी बारिश के कारण जो रूट बह गए थे, उन्हें यात्रा शुरू होने से पहले सही कर दिया गया है।'

फ़िल्ली यात्राओं से सबक लेते हुए यात्रा में कई लैंडिंग पॉइंट भी बनाए हैं। यात्रा के दौरान कई बार मौसम खराब होता है। कई बार लैंडस्लाइड भी होती है। इसे देखते हुए लिमिटेड यात्रियों के दर्शन धाम तक भेजे जाएंगे। जब एक जत्था दर्शन कर लौट आएगा, तब दूसरे को रवाना किया जाएगा। इससे न सिर्फ दर्शन आसान होंगे बल्कि केदारघाटी पर दबाव भी कम पड़ेगा।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व चेयरमैन अजेंद्र अजय कहते हैं, '2013 की आपदा के बाद लोग केदारनाथ आने से घबराने लगे थे। दहशत ऐसी थी कि 2014 में महज 39 हजार यात्री धाम पहुंचे। इसके बाद 2017 तक केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या 5 लाख तक भी नहीं पहुंची। केदारनाथ धाम आने में लोगों का भरोसा बंद, इसके लिए खुद पीएम मोदी ने यहां आकर रात बिताई। वो आपदा के बाद से 6 बार यहां के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को देखने आ चुके हैं।

'केंद्र सरकार के केदारनाथ रोडवेजल प्रोजेक्ट की मदद से यहां चौड़े यात्रा मार्ग, अस्पताल और चरहरों की अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। इसका असर अब पर्यटकों की बढ़ती संख्या में देखने को मिल रहा है।'

केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक, इस बार यात्रियों को केदारनाथ के दर्शन के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसके लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। यात्री टोकन में दिए गए समय के हिसाब से दर्शन कर रहे हैं। यात्रा रूट पर किसी भी यात्री की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत इलाज मिल रहा है।

यात्रियों के तुरंत ट्रीटमेंट के लिए केदारनाथ, केदारनाथ बेस कैम्प, लिंचोली, छोटी लिंचोली, रामबाड़ा, भीमबली, जंगल चट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में मेडिकल सेंटर बनाए गए हैं। यहां 24 घंटे डॉक्टर और फार्मासिस्ट रहते हैं। जरूरी दवाइयां भी हर वक्त उपलब्ध रहती हैं। सभी मेडिकल सेंटरों पर ऑक्सीजन की सुविधा भी रहती। केदारघाटी में अचानक मौसम बदल जाता है। ऐसे में ट्रैकिंग करते समय कोई भी घटना होने पर यात्री इंद्रानेट नेटवर्क की मदद से अपनी परेशानी बता सकेंगे और उन्हें तुरंत मदद मुहैया कराई जाएगी।

चरधाम यात्रा शुरू होने से पहले 28 अप्रैल को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी। अब भी वे लगातार इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चरधाम यात्रा बिना किसी बाधा के चल रही है।



